Central share of the Calamity Relief Fund of Mizoram to enable the State Government to undertake relief measures in the wake of natural calamities.

(b) As per the existing scheme of financing relief expenditure, the Central Government is to release an amount of Rs. 75.00 lakhs as its share of State Calamity Relief Fund during 1992-93.

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में गांव

2528. **डा० बापू कालदाते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 99 प्रतिशत गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मराठवाड़ा के किसानों को इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है ;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र से किस-किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है ; और

(घ) महाराष्ट्र को उन मांगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार पूरा करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) सूखे की परिस्थितियों में राहत उपायों पर व्यय को वहन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1991-92 के दौरान 576.58 करोड़ रुपये तथा 1992-93 के दौरान 212.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । प्राकृतिक आपदाओं की हालत में राहत व्यय के वित्त पोषण को वर्तमान स्कीम के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य को कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है ।

Drought in Rajasthan

2529. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the total amount requested by the Government of Rajasthan to meet the drought and what is the amount sanctioned by the Central Government so far and on what basis; and

(b) whether Government plan to decide special norms for allocation of funds for natural calamities like drought in Rajasthan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The Central Government has not received any memorandum from Government of Rajasthan seeking additional Central Assistance, over and above provisions of the Calamity Relief Fund, for relief measures in the wake of drought condition in the State.

(b) No, Sir.

कृषकों की दशा में सुधार लाने के लिए योजनाएं

2530. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कृषकों की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) और (ख) किसानों की स्थितियों में सुधार लाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों के प्रयासों में उनको सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित के बारे में हैं :-

1. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम जिसमें गेहूं, मक्का व कदन्नों के लिये मिनिकिट कार्यक्रम शामिल हैं।

2. समेकित चावल विकास कार्यक्रम।

3. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

4. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

5. गहन कपास विकास कार्यक्रम।

6. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

7. कम गहरे नलकूपों/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिये छोटे सीमांत किसानों को सहायता।

8 बागवानी फसलों के विकास के लिये योजनायें।

9. राष्ट्रीय बीज परियोजना, चरण–3.

10. वृहत फसल बीमा योजना और

11. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम।

किसानों को अपनी आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित करने के वास्ते इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

Financing of Agriculture Sector by World Bank

2531. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the specific areas in the agricultural sector for which the World Bank is financing and what are the names of the States in which projects (with names) have been taken up with the World Bank loan;

(b) whether the World Bank is extending the conditionalities for activities in the agricultural sector like privatisation, subsidy cuts and budget revive directly to the States through farm sector financing;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what are the implications involved and what is the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) A statement is laid on the Table of the Sabha. (See below).

(b) to (d) The State Governments cannot negotiate external assistance directly with the World Bank and, therefore, the question of the Bank extending any conditionalities directly to the states through farm sector financing does not arise.

Statement

The specific areas in the agricultural sector financed by World Bank through Department of Agriculture & Cooperation, Department of Animal Husbandry and Dairying and Department of Agricultural Research and Education are extension, dairy, agro-processing, research, seeds, watershed, emergency reconstruction and agricultural development.

The names of the states in which these projects are financed by the World Bank are given below:

State	Name of on-going Project
1. Andhra Pradesh	(i) National Dairy-II (Ln. 2893, Cr. 1859), (ii) National Seed Project-III (Cr. 1952), (iii) National Agriculture Research Project-II (Cr. 1631), (iv) National Cooperative Development Corporation-III (Cr. 1502), (v) A.P. Cyclone Emergency Reconstruction Project (Cr. 2179) and (vi) Rainfed Watershed Project (Cr. 1424).